



उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन

डॉ ललित कुमार आर्य

सीनियर एकेडमिक फैलो

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली

प्रोफेसर सुरक्षापाल

पूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष

शिक्षा विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

सार

उच्च शिक्षा को वर्तमान समय में शैक्षिक पिरामिड के रूप में माना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय विकास में योगदान देते तो व्यवस्था को खराब होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। अब सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास में अधिक से अधिक धन का निवेश करना होगा। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर खर्च में भारी कटौती इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार निजी संस्थानों को विनियमित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है। इसलिए, कुछ नियामक एजेंसियों का गठन किया जाना है जो गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और मुनाफाखोरी को रोकती हैं। एक तथ्य यह भी है कि निजी निवेशक संस्थान को घाटे में नहीं चलाएंगे। कम से कम, निजी संस्थानों को वाणिज्यिक होने की अनुमति दी जानी चाहिए यानी उन्हें ब्रेक-ईवन या एक छोटा सा उचित लाभ कमाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भूमिका

संस्थानों के तेजी से विकास, ज्यादातर निजी, ने योग्यता की सख्त जरूरत वाले छात्रों को आवश्यक राशि का भुगतान करने और उन्हें हासिल करने का प्रयास करने की अनुमति दी है।

इससे पहले, उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग, प्रबंधन और चिकित्सा जैसे अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में रही है। हालांकि, बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा में भारी निवेश करने में सरकार की अक्षमता ने इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए क्षेत्र को खुला छोड़ दिया है। अधिकांश निजी संस्थानों को सरकार से सहायता नहीं मिलती है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुदान का 52 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जाता है, जो एक लाख से कम छात्रों को पूरा करता है।

भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 60 प्रतिशत से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान निजी संस्थान हैं जिनमें लगभग 60 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं। निजी संस्थान एक छतरी के नीचे सभी स्नातक पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून, और कला और डिजाइन जैसे विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियामक ढांचे को सरल बनाया है।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह मानव विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में उच्च शिक्षा ने अभूतपूर्व विस्तार का अनुभव किया है। भारत ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों, डॉक्टरों, शिक्षकों और प्रबंधकों का उत्पादन किया है जिनकी पूरी दुनिया में बहुत मांग है। अब यह हमारी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता में शीर्ष दस देशों में से एक है, क्योंकि उच्च शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा द्वारा प्रदान किए गए जनशक्ति और उपकरणों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण। भारत पहले ही ज्ञान विस्फोट के युग में प्रवेश कर चुका है। इसने परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन से अपनी जबरदस्त क्षमता को साबित किया है।



वर्तमान में निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो उच्च शिक्षा तक पहुंच को संबोधित कर रहा है। इन निजी विश्वविद्यालयों का दुनिया भर में ऑफ कैंपस है। सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और आत्मसात करने के लिए संकायों को दुनिया भर में जाने का अवसर मिलता है। उनके पास एयर कंडीशनर क्लास रूम, हाई टेक लैब और विशाल परिसर क्षेत्र है। वे विश्व स्तरीय कंपनियों में प्लेसमेंट प्रदान करते हैं। वे व्यावहारिक आधारित, उद्योग उन्मुख शिक्षा पढ़ाते हैं और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवीन शिक्षण विधियों को लागू करते हैं।

निजी प्रदाता आमतौर पर एक लाभ के उद्देश्य से संचालित होते हैं, लेकिन वर्षों से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों की प्रकृति को धर्मार्थ माना है न कि लाभ के लिए। इसलिए, शिक्षा प्रदान करके अलौकिक या अवैध लाभ नहीं कमाया जा सकता है। यदि राजस्व अधिशेष उत्पन्न होता है तो इसका उपयोग शिक्षण संस्थान द्वारा अपने विस्तार और शिक्षा विकास के उद्देश्य के लिए किया जाना है।

अतीत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को अपने प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि योग्यता के सिद्धांत की बलि नहीं दी जानी चाहिए, यानी छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता या योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। एक निजी संस्थान का प्रबंधन योग्यता आधारित प्रवेश की परीक्षा को संतुष्ट करने के अधीन, छात्रों को प्रवेश देने में कोटा के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब था कि सरकार एक निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान पर अपनी आरक्षण नीति को अनिवार्य नहीं कर सकती थी। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) आदि के लिए सकारात्मक कार्रवाई है। इन संस्थानों में आरक्षण को अस्वीकार करने का औचित्य प्रवेश प्रक्रियाओं आदि के निर्धारण में उनके अधिकार और स्वायत्तता का अतिक्रमण था। ऐसा आरक्षण संस्था और सरकार द्वारा परस्पर निर्णय लेने पर ही संभव था।

उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन

शिक्षा एक ऐसा निवेश है जो न केवल देश की मानवपूंजी का निर्माण करता है अपितु एक राष्ट्र को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शिक्षा में उपयोग न केवल राष्ट्र को नवाचारी बनाता है अपितु शैक्षिक दृष्टि से उन्नयन कर देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से न केवल अधिगम की संस्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अपितु शिक्षण प्रक्रिया सुगम एवं सरल हो जाती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से छात्रों के लिए भी ई-पुस्तकें, परीक्षा के नमूने वाले प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, संसाधन व्यक्तियों से संपर्क की सरलता, शोधकर्ताओं आदि से सम्पर्क भी आसान हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि डिजिटल अधिगम्यता को संभव बनाना जिसके कारण छात्र अपने समय एवं सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ सकते हैं।

साथ ही साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा आपूर्ति यथा रेडियो, कम्प्यूटर, टेलीविजन आदि के माध्यम से सीखने वाले एवं अनुदेशक की एक भौतिक मशीन पर होने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सबसे बड़े शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग करने की शुरुआत हुई है इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप में कार्य किया है इसमें वीडियो, टेलीविजन, मल्टीमीडिया कम्प्यूटर साफ्टवेयर का उपयोग शामिल है जिसमें दृश्य एवं श्रव्य दोनो प्रकार समाहित हैं।

अतएव स्पेन्सर के शब्दों पर ध्यान देते हैं तो 'शिक्षा शरीर के अवयवों की उन्नति करती है तथा उन्हें जीवन के योग्य बनाती है।' शिक्षा जीवन को परिपूर्णता के साथ जीने का माध्यम है।

इसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी शिक्षा दर्शनों का विवेचन किया गया है। भारतीय दर्शनों में भी जीवन को समग्र दर्शन से देखने की वृत्ति रही है। भारतीय दर्शन के आलोक में शिक्षा जीवन का एकऐसा अध्यवसाय "जिसके द्वारा जीवन के आदर्श एवं मूल्यों को प्राप्त किया जाता है।

भारतीय शिक्षा दर्शन का प्रारम्भिक काल वैदिक युग से माना जा सकता है जिसमें श्रीमद्भगवतगीत का दर्शन



सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा दर्शन की दृष्टिसे भगवतीता अमूल्य निधि है। इसमें सभी प्रचलित मान्यताओं तथा सिद्धांतों का समाहार मिलता है। गीता के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को उस अज्ञान से मुक्त करना है जो भेद उत्पन्न करने वाला है तथा आत्मानुभूति में बाधक है। शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का सुन्दर विवेचन गीता में मिलता है वस्तुतः गीता के उद्देश्य केवल विद्यालयी शिक्षा तक सीमित नहीं है अपितु शिक्षा के कारण मनुष्य वर्तमान को अपूर्ण मानने लगता है वह उस अपूर्णता से ऊपर उठकर पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगता है। यही प्रगति का द्योतक है।

भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका को भी निरन्तर विकासशील पाते हैं। सूत्रकाल तथा लोकायत के बीच शिक्षा की सार्वजनिक प्रणाली के पश्चात् जैन एवं बौद्ध शिक्षा दर्शन में स्त्रियों एवं समाज के पिछड़े तबके को भी शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है।

भारत में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार किया गया है इसमें शिक्षा द्वारा नवाचारों को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा इंसान को बंधनों से मुक्त करे और उसे सक्षम बनाए। इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि शिक्षा रट्टा मारने वाली परम्परा से मुक्त हो। जिसमें शिक्षा को स्कूल की चारदीवारी के बाहर की दुनिया से जोड़ने की बात कही गयी है। इस नीति के बनने की प्रक्रिया में ब्लॉक और जिला स्तर से विचारों को आमंत्रित किया गया। इसके आलोचकों का कहना है कि केवल आम लोगों की राय के आधार पर किसी देश की शिक्षा नीति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसके लिए विशेषज्ञों की राय को भी महत्व देना चाहिए। काफी लम्बे समय तक नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी न होने के कारण भी असमंजस वाली स्थिति भी कायम थी। इसके कारण अखबारों में ड्राफ्ट के मुख्य बिन्दुओं के सार्वजनिक होने की खबरें छपीं।

नई शिक्षा नीति के सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च करने, पांचवीं के बाद बच्चों को फेल करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश को बढ़ावा देने और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम की भाषा के रूप में मातृभाषा (या क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा) को महत्व देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक आयोग बनाने की भी बात कही गई है, जिसका काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद करना होगा।

किसी देश का सामाजिक-आर्थिक विकास उसकी शिक्षा प्रणाली से सीधा जुड़ा होता है। हमारा देश निजी शिक्षण संस्थानों की उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वे बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं। छात्रों की। अच्छे निजी विश्वविद्यालयों को विकसित होने और अत्यधिक कुशल और पेशेवर मानव शक्ति के निर्माण के विशाल कार्य में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

मात्रात्मक विस्तार के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना महत्वपूर्ण है। प्रत्यायन संस्थानों की ऐसी गुणवत्ता को मापने का एक तरीका है। यह उन संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने की प्रक्रिया है जिन्हें कुछ निर्धारित मापदंडों के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए।

अनुसंधान कार्य

प्रस्तुत शोध कार्य में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 50 शिक्षकों को सम्मिलित लिया गया। इन सभी का चयन रैंडम सैपलिंग के तरीके से किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन सर्वेक्षण विधि की सहायता से किया गया है।

यह एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति थी।

जानकारी एकत्र करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग किया गया था।

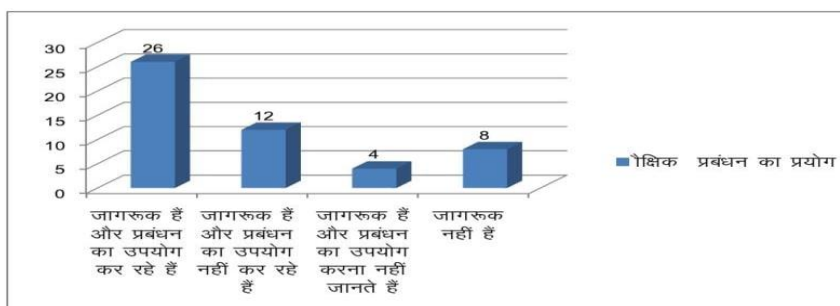
फॉर्म की सहायता से शोधकर्ता द्वारा एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रश्नावली तैयार की जाती है और लिंक

संभावित शिक्षकों को भेज दिया गया है।

शोध कार्य के परिणाम

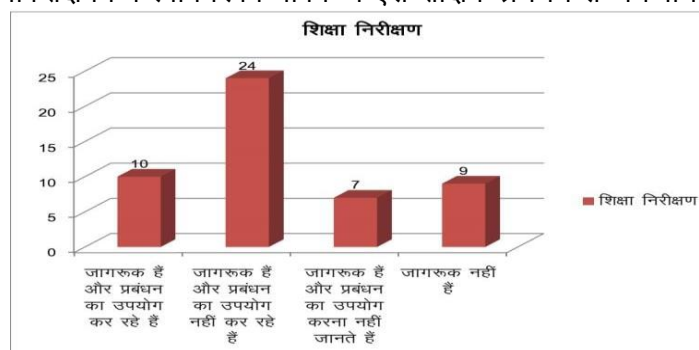
तालिका 1 भावी शिक्षकों के बीच जागरूकता

सं.	प्रबंधन	जागरूक हैं और प्रबंधन का उपयोग कर रहे हैं	जागरूक हैं और प्रबंधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं	जागरूक हैं और प्रबंधन का उपयोग करना नहीं जानते हैं	जागरूक नहीं हैं
1	शैक्षिक प्रबंधन का प्रयोग	26	12	4	8
2	शिक्षा निरीक्षण	10	24	7	9
3	विद्यालय प्रबंधन	14	26	4	6
4	शैक्षिक प्रबंधन	27	15	5	3



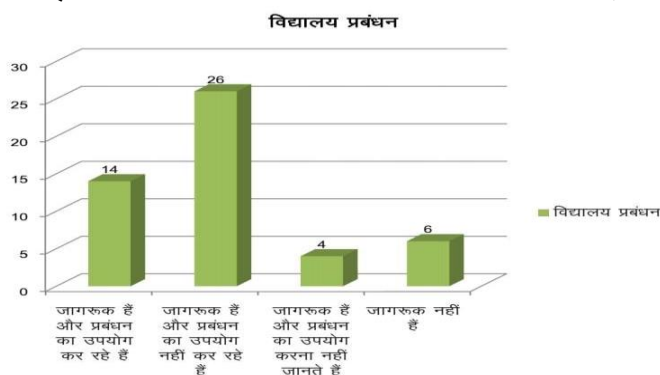
चित्र 1.1 भावी शिक्षकों के बीच शैक्षिक प्रबंधन की जागरूकता और उपयोग

चित्र 1.1 ने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जागरूकता और उपयोग पर भावी शिक्षक की प्रतिक्रियाओं को दिखाया। 52 प्रतिशत ने कहा कि वे शैक्षिक प्रबंधन का उपयोग करने के साथ-साथ जागरूक भी थे। 12 छात्र शिक्षकों ने व्यक्त किया कि वे शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जानते थे लेकिन इसका उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि शैक्षिक प्रबंधन का उपयोग कैसे किया जाता है। 4 छात्र शिक्षकों ने कहा कि वे जागरूक थे लेकिन इसका उपयोग करना नहीं जानते थे। 8 भावी शिक्षकों ने स्वीकार किया कि वे ऐसे शैक्षिक प्रबंधन से अनजान हैं।



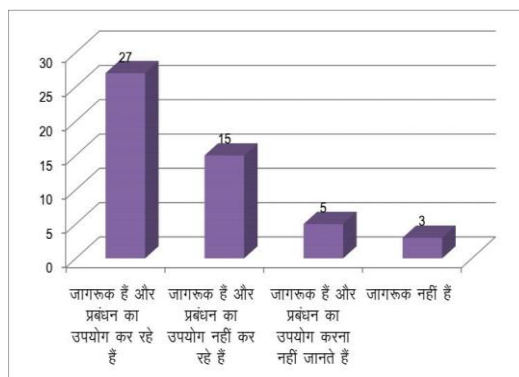
चित्र 1.2 भावी शिक्षकों के बीच शिक्षा निरीक्षण की जागरूकता और उपयोग

चित्र 1.2 में शिक्षा निरीक्षण की जागरूकता और उपयोग के प्रतिशत के उदाहरणों का विश्लेषण किया गया है बीस प्रतिशत (20 प्रतिशत) भावी शिक्षकों ने कहा कि वे शिक्षा निरीक्षण से अवगत थे और इसका उपयोग कर रहे थे। 48 प्रतिशत छात्र शिक्षकों ने कहा कि वे शिक्षा निरीक्षण के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन वे शिक्षा निरीक्षण का उपयोग करना जानते थे। 14 प्रतिशत ने कहा कि वे इसके बारे में जानते थे, लेकिन इसका उपयोग करना नहीं जानते थे। 18 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि वे शिक्षा निरीक्षण से अनजान थे।



चित्र 1.3 भावी शिक्षकों के बीच विद्यालय प्रबंधन की जागरूकता और उपयोग

चित्र 1.3 में विद्यालय प्रबंधन के बारे में जागरूकता और उपयोग पर भावी शिक्षक की प्रतिक्रियाओं को दिखाया गया है। 14 भावी शिक्षकों ने कहा कि वे विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानते हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं। 52 प्रतिशत ने कहा कि वे विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन वे विद्यालय प्रबंधन का उपयोग करना जानते थे। 8 प्रतिशत छात्र शिक्षकों ने कहा कि वे इसके बारे में जानते थे, लेकिन इसका उपयोग करना नहीं जानते थे। 12 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षुओं ने स्वीकार किया कि वे विद्यालय प्रबंधन से अनजान थे।



चित्र 1.4 भावी शिक्षकों के बीच शैक्षिक प्रबंधन की जागरूकता और उपयोग

चित्र 1.4 में शैक्षिक प्रबंधन की जागरूकता और उपयोग पर भावी शिक्षक की प्रतिक्रियाओं को दिखाया गया है। संभावित शिक्षकों में से 54 प्रतिशत ने कहा कि वे शैक्षिक प्रबंधन के प्रति जागरूक थे और इसका उपयोग कर रहे थे। 30 प्रतिशत भावी शिक्षकों ने कहा कि वे शैक्षिक प्रबंधन के प्रति सचेत थे, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन वे शैक्षिक प्रबंधन का उपयोग करना जानते थे। भावी शिक्षकों में से 10 प्रतिशत ने कहा कि वे इसके प्रति सचेत थे, लेकिन इसका उपयोग करना नहीं जानते थे। संभावित शिक्षकों में से 6 प्रतिशत ने माना कि उन्हें इस



तरह की शैक्षिक प्रबंधन की जानकारी नहीं थी।

निष्कर्ष

अधिकतर शिक्षकों ने कहा कि वे शैक्षिक प्रबंधन का उपयोग करने के साथ-साथ जागरूक भी थे। कम छात्र शिक्षकों ने व्यक्त किया कि वे शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जानते थे लेकिन इसका उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि शैक्षिक प्रबंधन का उपयोग कैसे किया जाता है।

बीस प्रतिशत भावी शिक्षकों ने कहा कि वे शिक्षा निरीक्षण से अवगत थे और इसका उपयोग कर रहे थे। अधिकतर छात्र शिक्षकों ने कहा कि वे शिक्षा निरीक्षण के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन वे शिक्षा निरीक्षण का उपयोग करना जानते थे।

संभावित शिक्षकों में से अधिकतर ने कहा कि वे शैक्षिक प्रबंधन के प्रति जागरूक थे और इसका उपयोग कर रहे थे। अत यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षक शैक्षिक प्रबंधन के प्रति जागरूक हैं।

संदर्भ

- 265वीं रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांग 2015-16 (मांग संख्या 60 मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति अप्रैल 23 2015।
- उच्च शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग व्यय बजट।
- एक नजर में शिक्षा 2020 आर्थिक सहयोग और विकास संकेतकों के लिए संगठन 2010।
- उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (अनंतिम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2015।
- उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नवंबर 2020
- प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। 2019 की रिट याचिका (सिविल) 416।
- भारतीय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद